महारेरा ने बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को जल्दी ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट दिलाने के लिए एक से अधिक एजेंसियों को नियुक्त करने की सिफारिश की

एक ही व्यक्ति के पास प्रोजक्ट्स की ओसी देने का एकाधिकार तोड़ने का सुझाव

700 प्रोजेक्ट्स के डेवलपर्स ने ओसी के लिए आवेदन समय पर किया, लेकिन उन्हें देरी से ओसी प्राप्त हुई

नई दिल्लीः महारेरा के चेयरमैन श्री गौतम चटर्जी का यह कहना है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट प्रदान करने का काम एक से अधिक एजेंसियों को दिया जाना चाहिए। ऐसा होने से एक ही अधिकारी के पास ओसी प्रक्रिया का एकाधिकार नहीं रहेगा, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। महारेरा चेयरमैन ने नई दिल्ली में 13 और 14 फरवरी 2019 को क्रेडाई द्वारा आयोजित 'यूथकॉन-19' में बोलते हुए उपरोक्त विचार व्यक्त किये हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ महाराष्ट्र में 700 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके डेवलपर्स ने समय पर सभी दस्तावेज जमा करके ओसी के लिए आवेदन किया था, लेकिन एकमात्र अधिकारी के कारण इनकी सभी प्रयास रुके पड़े थे क्योंकि सिर्फ उसी अधिकारी को ओसी देने का अधिकार है।

श्री गौतम चटर्जी ने कहा कि, सभी मंज़ूरी एक ही प्लानिंग विभाग द्वारा दी जाती है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि उसी प्लानिंग विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले इस अधिकारी ने ओसी प्रदान करने के लिए इतना वक्त क्यों लगाया। जबकि इससे संबंधित प्रोजेक्ट का निर्माण कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के अनुसार किया गया था। उन्होंने यह सुझाव दिया कि विभिन्न एजेंसियों को ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट्स प्रदान करने का अधिकार दिये जाने की प्रक्रिया में प्लानर्स एवं आर्किटेक्ट्स का एक पैनल शामिल होना चाहिए, जो पर्याप्त जांच के बाद निर्माण प्रोजेक्ट्स को ओसी प्रदान कर सके। इससे एकमात्र अधिकारी का एकाधिकार तोड़ा जा सकेगा, जो बिना किसी कारण ओसी को रोक कर रख सकता है और इसके लिए उसका ढुलमुल रवैया ही जिम्मेदार है।

महाराष्ट्र रेरा के प्रमुख श्री गौतम चटर्जी ने कार्यक्रम में रेरा के बारे में विभिन्न जानकारियां प्रदान की। इस मौके पर कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश रेरा प्रमुख श्री राजीव कुमार, मध्य प्रदेश रेरा प्रमुख श्री एंथोनी डे सा और हरियाणा रेरा प्रमुख श्री के. के. खंडेलवाल भी उपस्थित थे।

महारेरा चेयरमैन ने यह प्रतिक्रिया क्रेडाई एमसीएचआई के प्रेसिडेंट श्री नयन शाह के सवाल के जवाब में दी, जिनका कहना था कि महाराष्ट्र के डेवलपर्स उस दिन के इंतज़ार में हैं जब मंज़ूरी देने वाले अधिकारी भी रेरा के दायरे में आएँगे।

For more detail
Rajesh Prajapati PR Committee Chairman - CREDAI MCHI-

PR Team
Bhagyashree Khedkar 9833189357
Charmi Masan 9833189357